Sl. No.	State/UT	Nos. Fig. upto
22	Tamil Nadu	55
23	Tripura	2
24	Uttar Pradesh	786
25	West Bengal	237
	UNION TERRITORIES	
1	A & I lands	Nil
2	Chandigarh	Nil
3	Dadra & Nagar Haveli	Nil
4	Daman & Diu	Nil
5	Delhi	68
6	Lakshadweep	Nil
7	Pondicherry	4

NOTE: The figures are based on monthly crime statistics and may be treated as provisional.

Atrocities on Minorities

545. KUMARI ALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that there is an increase in the incidents of atrocities on the minorities in the different part of the country;

(b) if so, what are the details thereof and the areas where such incidents have taken place recently; and

(c) what are the steps being taken by Government to prevent such incidents?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (c) The registration investigation detection and prevention of crime is the responsibility of the State Governments/Union Territory Administrations. Details of atrocities are not compiled by the Central agencies.

अल्पसंख्यकों का संहार

546. **मौलाना अबेदुल्ला खान आजमी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अयोध्या विवाद के संदर्भ में घटी ताजी घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में साम्प्रदायिक शक्तियों द्वारा अल्पसंख्यकों के संहार के खतरे के बारे में सरकार को जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) : (क) और (ख)

हमारे देश में अल्पसंख्यकों को ऐसा कोई खतरा नहीं है । केन्द्र सरकार देश में अल्पसंख्यकों के कल्याण और हितों की सदैव रक्षा करती आ रही है । साम्प्रदायिक सौहार्दता को बढावा देने के लिए राज्य सरकारों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं । अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु एक 15 सूत्री कार्यक्रम सभी राज्य सरकारों को परिचालित किया गया । हाल ही में 2 नवम्बर, 1991 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद् की बैठक में राम जन्म भूमि बाबरी मस्जिद के संदर्भ में साम्प्रदायिक स्थिति पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ, तथा परिषद ने राजनीतिक दलों सहित सभी संबंधित धार्मिक नेताओं, जन-संपर्क माध्यमों तथा अन्य संगठनों से संयम बरतने तथा इस ढंग से कार्य करने का आह्वान किया है जिससे सभी समुदायों के बीच सौहार्दता तथा सद्भावना बढे ।

बंगलादेश को नर-कंकालों की तस्करी

548. **चौधरी हरि सिंह :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 सितम्बर, 1991 के "हिन्दुस्तान", नई दिल्ली में प्रकाशित इस आशय के समाचार की ओर दिलाया गया है कि पश्चिमी बंगाल से बंगलादेश को नर-कंकालों की तस्करी की जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस अवैध व्यापार को रोकने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और

(घ) इस संबंध में अब तक कितने व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही की गयी है ?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जकब) : (क) जी, हां, श्रीमन् ।

(ख) से (घ) पश्चिम बंगाल से बंगलादेश को मानव-कंकाल की तस्करी करने का कोई मामला जानकारी में नहीं आया है । फिर भी, तस्करी, घुसपैठ तथा अन्य सीमा पार करने संबंधी अपराधों की रोकथाम करने के लिए, गस्तानाकाबंदी को बढा दिया गया है । बेहतर निगरानी करने के लिए, निगरानी बुर्जों का निर्माण किया गया है, तथा बेहतर प्रभावी निगरानी तथा तत्पर कार्रवाई करने के लिए जीपों/मोटर-साईकिलों पर चलती-फिरती गश्त गहन कर दी गई है ।

Darbars in Punjab

548. SHRI S. S. AHLUWALIA: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Governor of Punjab has recently started holding 'darbars' for solving the problems of citizens;

(b) if so, what are the main achievements of such darbars;

(c) what is the number of cases solved so far in these darbars;

(d) whether this system has been approved by Government; and

(e) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF SATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): (a) to (t) As part of the various measures initiated to bridge the gap between the administration and the people and to restore the confidence among the people, the Governor of Punjab alongwith senior officers of the State Government has been touring different parts of the State and holding public meetings and rallies where genuine grievances of the people are attended to. The exact number of cases solved during such meetings is not, however, readily available.